लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2507

14 दिसम्बर, 2015 को उत्तर के लिए

सेल का कार्यनिष्पादन

2507. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री सुधीर गुप्ता:

डॉ. वीरेन्द्र कुमार:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्रीमती कोथापल्ली गीता:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) को पिछली तिमाहियों में भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सेल के ढांचे की समीक्षा के लिए एक बाहरी परामर्शदाता को नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इसकी बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने हेतु मूल्य वर्धित उत्पादन, आक्रमक विपणन को बढ़ाने, उत्पादन लागत और माल सूची में कमी लाने हेतु बेहतर परिचालन प्रबंधन हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): वर्ष 2015-16 की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान सेल ने 1378 करोड़ रूपए की कुल हानि अर्जित की है। हानियों के मुख्य कारण बिक्रेय इस्पात की बिक्री से होने वाली शुद्ध प्राप्ति में कमी, लौह अयस्क पर अधिकार शुल्क के खर्च में बढ़ोतरी, विदेशी विनिमय दरों में परिर्वतन तथा ब्याज और मूल्यह्रास जैसे पूंजीगत खर्च का बार बार होना इत्यादि हैं।

(ग) और (घ): इस्पात मंत्रालय ने सेल की समग्र कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक बाहरी परामर्शदाता को नियुक्त करने का निर्णय लिया है ताकि इसके कार्य निष्पादन में सुधार हो सके।

(ड.) और (च): सेल अपने उत्पादन को बढ़ाने, पुरानी प्रोद्योगिकियों को हटाने, ऊर्जा कार्यकुशलता में सुधार करने और अपने उत्पादों के बीच मूल्य वर्द्धित उत्पादों की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रमुख आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की वित्तीय स्थिति को पूर्वस्थिति में बहाल करने के लिए इसने शीघ्रता आधार पर एक आमूलचूल परिर्वतन की योजना तैयार की है जिसमें व्यापक रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा को अधिकतम बनाना, उत्पाद मिश्रण को समृद्ध बनाना और नई सुविधाओं से उत्पादन बढाना, प्रचालनगत क्षमता में सुधार लाना और लागत में कमी करना, अपेक्षाकृत कम कुशल तरीकों से होने वाले उत्पादन को युक्तिसंगत बनाना, वसूलियों में सुधार के लिए विपणन पहल करना, खर्च पर नियंत्रण करना और पूंजीगत खर्च को वरीयता देना इत्यादि शामिल है।

***